सम्पादक के नाम

निजी स्कूलों में लूट की दास्तान

अनिता बड़खल

सभी माता-पिता अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मेरे बच्चे पढ लिखकर एक सफ़ल इंसान बने और अपनी जिंदगी बेहतर से बेहतर तरीके से जिये। लेकिन शिक्षा देश के प्रत्येक नागरिक को अंधेरे से रोशनी की तरफ़ ले जाने का हथियार है उसको विवेकशील बनाती है। लेकिन आज जिसके पास पैसा जितना उसका ज्ञान उतना वह विवेकशील, आज शिक्षा पैसे का खेल बन चुका है। जिस शिक्षा का वादा आजादी की लड़ाई में किया गया था आज वह कहां है। सरकारी स्कूलों की हालत तो इतनी बदतर है कि बच्चे 8-9 तक पहुंचकर हिन्दी तक नहीं पढ़ पाते। वे बेसिक गुणा-भाग तक नहीं कर पाते। अब-तक लगभग एक लाख सरकारी स्कूल बन्द हो चुके हैं।

बन्द होने वाले स्कूलों के बच्चे या तो प्राइवेट में जाने को मज़बूर हैं या फ़िर अनपढ़ रहने को संयुक्त राष्ट्र संघ के मिलेनियम गोल्ड 2015 तक देश के सभी बच्चों को शिक्षित करने का फ़ैसला किया था। लेकिन लगभग साढे चार करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा से महरूम है। बच्चों में सबसे ज़्यादा संख्या एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम बच्चों की है। जब सरकार ने सबको शिक्षित करने के वादे से मुंह मोड़ लिया तो पूंजीपतियों के लिये शिक्षा भी धन्धे का एक साधन बन गया है। जिसका नतीजा यह है कि शिक्षा के बाजार में अंधी लूट मची है।

हर माता-पिता यह चाहता है कि उसका बच्चा पढ़-लिखकर अनपढ़ न रहे फ़र्राटेदार अंग्रेजी बोले तथा बड़ा होकर बड़े ओहदे ले। इसी सपने को लेकर वह प्राइवेट स्कूल की तरफ़ दौड़ता है जहां उसे बच्चे के स्किल के पर लूटा जा रहा है। अभिभावक अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने को मजबूर है।

मैं भी इसी लुट से लूटी हुई एक मां हूं। जहां मैंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिये सेक्टर 21 के एक नामी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाया लेकिन आज मैं उसके खर्चों तथा ऊंची दुकान फ़िके पकवान से पीड़ित हूं। जब मैंने दाखिला दिलवाया था तो डेवलपमेंट फ़ीस के नाम पर 6500 दो महिने की एडवांस फ़ीस ली गई थी और किताब, युनिफ़ोर्म आदि-आदि के नाम पर अलग से वसूली होती है।

लेकिन अगर मनोवैज्ञानिक ढंग से सोचे तो ये रंगहीन किताबें बच्चों को कितना आकर्षित करेगी। उसके मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव डालेगी? पहले किताबे दिखाने, पढाई को किस तरह से कराया जायेगा जब पूरा स्कूल विदेशी ढाचागत हो तो बच्चों की किताबों के मामले में निरसता क्यों है। पांच दिन में दो तरह की बर्दी है। दो तरह के जूते, दो तरह के जूराब है। एक एप्रन है।

हर महिने -600-700 रुपये का आर्ट, फ्राफ्ट का सामान तथा एक पेंसिल तथा एक रबड़ का डब्बा है एक रंग का डब्बा है। मैं सोचती हूं कि मेरा बच्चा सप्ताह में एक पेंसिल तथा रबड़ खर्च नहीं कर पाता तो क्या स्कूल में खर्च करता होगा। हमने अपने बच्चे का एडमिशन 30 मार्च 2018 को कराया था। तथा वह एक अप्रैल से स्कूल जा रहा है एक महिना 15 दिन वह स्कूल गई और फ़िर दो महिने की छुट्टियां और छुट्टियों की फ़ीस आ गई। सोची चलो थोड़ा सा आराम मिल जायेगा और कहीं घूम-फ़िर आयेंगे लेकिन होम वर्क भी माताओं के लिये सर दर्द होता है। वो होलीढेय होम वर्क बच्चों के लिये नहीं ऐसा लगता है माताओं के लिये होता है। एक बच्चा जो अ से अनार सीख रहा है वह कोई भी मॉडल कैसे बना सकता है? मैंने सोची कि इसका मॉडल नहीं बनाऊंगी। पर मेरे बच्चे ने कई बार यह मांडल बनाने के लिये बोला पर मैं लगातार टालती रही अन्त में मैंने वह नहीं बनाया। जब स्कूल खूले तो मेरा बच्चा स्कूल गया तो देखा कुछ अभिभावकों ने यह मॉडल बनाया था। जब बच्चा घर आया तो सबसे पहले उसने मुझसे यही पूछा कि आपने मेरा मॉडल क्यों नहीं बनाया? मैं इस बात को धीरे-धीरे भूल गयी।

बरसात के दिनों में रेन कोट तथा मगंने का नया नोटिस और उसके कुछ ही दिन बाद सफ़ेद कमीज तथा फुल पैंट का नोटिस। हमने सोचा कि सर्दियों के लिये यूनिफ़र्म है। फ़िर पता चला कि वह तो बस 15 दिनों के लिये थी। अक्तूबर लास्ट में फ़िर नोटिस आया कि गरम कमीज लेनी है और उसके साथ एक फुल स्वेटर। जो आस-पास के बाजार से लाये तो मात्र 150 रुपये का है लेकिन स्कूल वालों की एक दुकान बताई हुई है जहां से स्कूल का सारा सामान मिलता है। वहां पर इस स्वेटर का रेट 350 रुपये था।

सोचें कि 150 वाला भी तो अपना मुनाफ़ा कमा रहा है तो स्कूल वालों की दुकानदार कितना मुनाफ़ा कमा रहा होगा? सर्दी की गर्म जकेट जो ऑडर पर बनाई जाती है उसका रेट था 700 रुपये तथा साथ में गर्म जुराब जो बाहर 20 तथा दुकान से 50 रुपये। इन सब खर्चों ने तो इतना परेशान कर दिया कि अब हम सोचते हैं कि अपने बच्चे को सरकारी स्कूल केन्द्रीय विद्यालय में डाल दे। मैं केवी के बच्चों को ट्यूशन पढाती हूं तो उन्हें हिन्दी भी ठीक से नहीं आती है इसलिये केवी में भी भेजने में डर लगता है। इन प्राइवेट की लूट का हद तो तब हो गई जब मेरे फ़ीस के 700 रुपये काट लिये गये। 1 नवम्बर-13 तक छुट्टी था तथा 22 से 26 नवम्बर तक छुट्टी, इतनी छुट्टियों में कब स्कूल फ़िस का चलान आया कि पता ही नहीं चला।

सब टेंशन में निकल गया जनवरी में जब मेरा बच्चा स्कूल गया और जनवरी, फ़रवरी, मार्च तथा परीक्षा. फीस का चालान आया तो उसको सुबमीट करने के लिये स्कूल गयी तो पता चला कि नवम्बर की फ़ीस जमा नहीं हुई है। दी गई दिनांक के बाद फ़ीस जमा कराते हैं तो 10 रुपये रोज के हिसाब से फ़ाइन लगता है। 100 रुपये हमारे जनवरी फ़रवरी मार्च की लेट फ़ीस के कट गये तथा 600 रुपये जनवरी के कट गये और सूचित भी नहीं किया गया। जब मैने उनसे बात करी तो मुझसे बोला गया कि आपकी जिम्मेदारी है समय से फ़ीस जमा करना। मैने गुस्से से पूछा कि आपने फ़ोन क्यों नहीं किया तो बताया गया आपका फ़ोन बंद आता है जबकि बच्चे की क्लास टीचर हमेशा उसी पर बात करती है। स्कूल वालों के पास सूचित करने का एक ही जरिया है बच्चे की डायरी तथा उसकी क्लास टीचर।

स्कूल का काम किसी भी तरीके से पैसा बनाना है। जब स्कूल तीन महीने की फ़ीस एडवांस लेता है तो क्या उसका ब्याज हमें दिया जाता है। किसी के घर में अगर कोई हादसा हो जाए तो स्कूल कोई भावानात्मक लगाव नहीं रखता उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे कमाने से मतलब है।

चन्दा कोचर पर एफआईआर से सीबीआई पर क्यों भड़के जेटली? किसे बचा रहे हैं?

गिरीश मालवीय

आपने ऐसा कितनी बार सुना है कि सरकार का सबसे ताकतवर कैबिनेट मंत्री अपनी ही जांच एजेंसी की खुलेआम आलोचना कर रहा हो? साफ बात यह है कि मामला जो नजर आ रहा उससे कही अधिक पेचीदा है!

धोखाधड़ी के मामले में ICICI बैंक की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर के खिलाफ चल रही जांच के मामले में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने सीबीआइ को ही निशाने पर ले लिया।

जेटली ने लिखा, 'पेशेवर जांच और जांच में दुस्साहस के बीच आधारभूत अंतर है। हजारों किलोमीटर दूर बैठा, मैं जब ICICI केस में संभावित लक्ष्यों की सूची पढ़ता हूं तो एक ही बात मेरे दिमाग में आती है कि लक्ष्य पर ध्यान देने की जगह अंतहीन यात्रा का रास्ता क्यों चुना जा रहा है?'

जेटली ने यह टिप्पणी ऐसे वक्त की है, जब एक ही दिन पहले सीबीआई ने चंदा कोचर के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में बैंकिंग क्षेत्र के के.वी.कामथ तथा अन्य को पूछताछ के लिये नामजद किया है।

ये अन्य कौन है इसके बारे में किसी मीडिया खामोश है! एकमात्र नाम के.वी. कामथ का सामने आ रहा है के वी कामथ भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के दिग्गज हस्ती है और ICICI बैंक के पूर्व चेयरमैन रह चुके है।

ICICI ग्रुप कभी CEO बनाने की फैक्ट्री था। ICICI में काम करने वाले कई कर्मचारी आज देश में बड़े पदों पर काम कर रहे हैं। कामथ ने ही देश की दो सबसे बड़ी महिला बैंकर्स चंदा कोचर और शिखा शर्मा को ग्रुप किया था। इन दोनों ने ICICI ग्रुप में केवी कामथ की मेंटरशिप में लंबे समय तक काम किया है। शिखा शर्मा पर भी एक्सिस बैंक के सीईओ रहते भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं।

कामथ ने एक बार कहा था- 'मैने जितने लोगों को सिखाया उसमें चंदा मेरी फेवरेट है।' जब कामथ 2009 में रिटायर हुए तो चंदा कोचर को ही उनका उत्तराधिकारी बनाया गया।

कामथ भारतीय उद्योग जगत में बहुत प्रभावशाली हस्ती माने जाते हैं। कहा जाता हैं कि जब धीरूभाई अंबानी की विरासत का बंटवारा करने का प्रश्न आया तो कोकिलाबेन ने दोनों बेटों के बीच मध्यस्थता कराने के लिए जिन लोगों को चुना था उसमें कामथ भी एक थे। के वी कामथ ने तब यह सुझाया था कि आरआईएल और आईपीसीएल का विलय करके एक कंपनी बनायी जाए और फिर उसे दो हिस्सों में करके दोनों भाइयों मुकेश अंबानी ओर अनिल अंबानी में बराबर बांट दिया जाए. इस सुझाव पर मुकेश अंबानी को आपत्ति थी, लिहाज़ा, आरआईएल और आईपीसीएल मुकेश के हिस्से में आयीं. रिलायंस इन्फोकॉम (कम्युनिकेशन), रिलायंस कैपिटल और रिलायंस एनर्जी की कमान अनिल के हाथों में गयी। उसके बावजूद 2005 में हुए बहुप्रचारित बंटवारे के पहले कामथ ने दोनों भाइयों के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

साफ है कि कामथ उद्योग और बैंकिंग के क्षेत्र में बहुत तगड़ी पकड़ रखने वाले शख्स है। मोदी सरकार ने के.वी कामथ को 'ब्रिक्स' देशों द्वारा स्थापित किए जा रहे 50 अरब डॉलर के 'न्यू डिवेलपमेंट बैंक' (एनडीबी) का प्रमुख भी नियुक्त किया है। ब्रिक्स में 5 उभरते विकासशील देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, इन्ही देशों ने पिछले साल एनडीबी स्थापित करने पर समझौता किया था। समझौते के मुताबिक भारत को इस बैंक का पहला अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार मिला था, इसलिए इस पद पर कामथ की नियुक्ति की गई है और अब उन्हीं कामथ से सीबीआई पूछताछ कर रही है

लेकिन सीबीआई सही कर है, क्योंकि वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धूत से जब चंदा कोचर के बारे में पूछा गया तो धूत ने कहा था कि जिस समिति ने विडियोकॉन ग्रुप के 3,250 करोड़ के कर्ज को मंजूरी दी थी, उसके 12 सदस्यों में से चंदा कोचर मात्र एक सदस्य थी। उन्होंने यह महत्वपूर्ण दावा भी किया था कि जिस समिति ने यह लोन मंजूर किया है उसके अध्यक्ष के.वी. कामथ थे और आईसीआईसीआई बैंक के फॉर्मर चेयरमैन के. वी. कामथ को वह पर्सनली जानते भी थे वह उनके साथ लंच पर जाया करते थे।

यानी भांग पूरे कुँए में ही घुली हुई थी, इसलिए सबकी जाँच होना चाहिए इसमे कुछ भी ग़लत नही है लेकिन जो रिलायंस के इतने करीबी हो उसे मोदी के केंद्रीय मंत्री क्यो न बचाएं। चन्दा कोचर का रिलायंस से भी नाता है। चंदा की बेटी आरती रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम करती हैं। उनकी शादी आदित्य काजी से हुई है। आदित्य का पूरा परिवार उद्योगपति अंबानी फैमिली का करीबी है। आदित्य और आरती फिलहाल मुंबई में रिलायंस कंपनी में कार्यरत हैं। आदित्य के पिता समीर काजी और मां राधिका को अंबानी परिवार के करीबी माना जाता है।

सीबीआई की समझ

कोचर मैम ने डूबते हुए धुत सर को लोन दिया.. ठीक है!

धुत सर चुकाए नहीं.....ठीक है!

CBI ने लम्बी जांच पड़ताल के बाद इनलोगन पर स्नढ्ढक्रकर दिया... ठीक है!

हजारों मील दूर बैठ के बीमारी का इलाज करा रहे वित्त मंत्री को CBI कां काम "इन्वेस्टिगेटिव अडवेंचरिज्म" दिखा.

ठीक है! FIR पर साइन करने वाले CBI वाले अधिकारी का डिपार्टमेंट बदलकर झारखंड भेज दिया गया....ठीक है!

ई ससरे CBI वालों को कब समझ मे आएगा कि एडवेंचर लालू जैसे विरोधियों के विरुद्ध दिखाने की चीज है..... कोचर और धूत जैसे मालिकों के विरुद्ध नहीं ठीक है!

- शशि भूषण

भारत रत्न पाने वाले नानाजी देशमुख ने ठहराया था सिखों के नरसंहार को जायज

जनचौक ब्यूरो

मोदी सरकार ने देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न एक ऐसे शख्स को दिया है जिसने 1984 के सिख विरोधी दंगों का समर्थन किया था। उन्होंने इस काम को पर्दे के पीछे से नहीं बल्कि खुलेआम लेख लिख कर किया था। एक ऐसे दौर में जबकि सिख नरसंहार के सबसे बड़े चेहरे और कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को अदालत से सजा मिल रही है। तब ऐसे समय में नरसंहार के पक्ष में खड़े होने वाले देशमुख को भारत रत्न देने के सरकार के फैसले ने उसके असली चेहरे का पर्दाफाश कर दिया है।

31 अक्तूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश और उसके विभिन्न हिस्सों में सिख विरोधी भीषण नरसंहार हुए थे। इन घटनाओं में हजारों निर्दोष सिखों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इस हैवानी क्रूरता के सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं और बच्चे हुए थे। ऐसे मौके पर जबकि देश का बुद्धिजीवी तबका और इंसानी समाज पीडित समुदाय के साथ खड़ा था। तब नानाजी देशमुख ने 8 नवंबर 1984 को एक लेख लिखकर न केवल इन दंगों का समर्थन किया था बल्कि उन्होंने आत्मरक्षा में खड़े हुए सिखों को लानतें भेजी थीं। इतिहासकार शमसुल इस्लाम के हवाले से आयी इस जानकारी में बताया गया है कि नानाजी देशमुख के इस लेख को देश के रक्षामंत्री रहे जार्ज फर्नांडिस ने अपनी साप्ताहिक पत्रिका "प्रतिपक्ष" में 25 नवंबर 1984 को पकाशित की थी। इसमें देशमुख ने गांधी जी की हत्या के समय आरएसएस द्वारा बरते गए धैर्य से सिखों को बाकायदा नसीहत लेने की सलाह दी है।

पूरे लेख में कहीं भी हिंदुओं या फिर सिखों के ऊपर हमला करने वाले दंगाइयों को दोषी नहीं ठहराया गया है। बल्कि बार-बार इंदिरा गांधी की तारीफ में कसीदे पढ़े गए हैं और हमलों को हिंदुओं की स्वाभाविक गुस्से की अभिव्यक्ति का हिस्सा बताया गया है। पत्रिका में भी फर्नांडिस ने इसे "इंका-आरएसएस गठजोड़" यानी इंदिरा कांग्रेस और आरएसएस के बीच गठजोड़ शीर्षक से छापा है। साथ ही संपादक के हवाले से लेख को छापने के पीछे के मकसद को भी साफ कर दिया गया है। जिसमें कहा गया है कि "लेखक को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चिंतक विचारक एवं नीति निर्देशक माना जाता है। प्रधानमंत्री हत्या के बाद उन्होंने इस दस्तावेज को प्रमुख राजनेताओं के बीच बांटा है। इसका एक ऐतिहासिक महत्व है, इसी कारण हमने अपने साप्ताहिक के नियमों का उल्लंघन कर इसे प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। यह दस्तावेज इंका और आर.एस.एस. के संबंधों के नए समीकरण को उजागर करता है।..."

दरअसल उस समय जार्ज विपक्ष में होने के चलते कांग्रेस और बीजेपी दोनों के विरोधी थे। और उसी विचारधारा के तहत उन्होंने संघ और कांग्रेस दोनों की घेरेबंदी की है।

लेख में नाना जी देशमुख द्वारा कही गयी मुख्य बातें -

1- सिखों के नरसंहार के पीछे किसी समूह या फिर समाज विरोधी तत्व का हाथ नहीं था। बल्कि ये हिंदुओं की स्वाभाविक नाराजगी का नतीजा था।

2- देशमुख श्रीमती इंदिरा गांधी के दो सुरक्षाकर्मियों को सिख समुदाय से अलग नहीं कर पाते हैं। पूरे लेख में उन्हें इस रूप में पेश किया गया हैं जैसे कि उन्हें पूरे सिख समुदाय का जनादेश हासिल था। इसलिए सिखों पर हमला जायज है।

3- लेख के मुताबिक सिखों ने खुद ही इस हमले को आमंत्रित किया है। ये ठीक कांग्रेस तर्ज पर था जिसने सिखों के नरसंहार को जायज ठहराने के लिए यही तर्क दिया था।

4- उन्होंने आपरेशन ब्लू स्टार की जमकर तारीफ की है और उसका विरोध करने वालों को राष्ट्रद्रोही के तौर पर पेश किया है। जब देश में हजारों की तादाद में सिख मारे जा रहे थे तब वो देश को सिख आतंकवाद से सावधान रहने की चेतावनी दे रहे थे। जो अपने आप में सिख हत्याओं को जायज ठहराने जैसा था।

5- उनके मुताबिक ये सिख समुदाय ही था जो पंजाब में हिंसा के लिए जिम्मेदार था।

6- उनके पूरे लेख में इस बात की वकालत की गयी है कि सिखों को आत्मरक्षा में कुछ नहीं करना चाहिए था। बल्कि उन्हें हमलावर भीड़ के सामने सहनशील बने रहकर उनके साथ सहिष्णुता से पेश आना चाहिए था।

7- उनके मुताबिक नरसंहार के लिए हिंसक भीड़ नहीं बल्कि सिख बुद्धिजीवी जिम्मेदार हैं। जिन्होंने सिखों को एक कट्टर समुदाय में बदल दिया और उन्हें उनकी हिंदू जड़ों से काट दिया। इस तरह से उन्होंने खुद ही राष्ट्रवादी भारतीयों से हमलों को आमंत्रित किया। दिलचस्प बात ये है कि देशमुख को हिंदुओं के कट्टरपन से कोई एतराज नहीं है।

8- उन्होंने इंदिरा गांधी को देश को एक रखने वाली अकेला नेता करार दिया है। और उनकी हत्या होने पर उसकी प्रतिक्रियास्वरूप इस तरह की हत्याओं को बहुत स्वाभाविक बताया है।

9- उन्होंने उस समय प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी को पूरा समर्थन देने और उनके साथ खड़े होने की अपील की है। वो भूल गए थे कि ये राजीव गांधी ही थे जिन्होंने कहा था कि "जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती का हिलना स्वाभाविक हैं।"

10- हैरानी की बात ये है कि देशमुख ने सिखों के नरसंहार की तुलना महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ पर हुए हमले से कर डाली है। उन्होंने बाकायदा उदाहरण देकर बताया है कि किस तरह से उस समय आरएसएस ने सहनशीलता दिखायी थी। और बगैर किसी प्रतिकार के सब कुछ सहन किया था। ठीक उसी तरह से इस मौके पर सिखों को भी बगैर किसी प्रतिक्रिया के सब कुछ सह लेना चाहिए।

11- पूरे लेख में देशमुख द्वारा किसी एक भी जगह सिखों के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए उपाय करने की जरूरत पर बल नहीं दिया गया है। न ही उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस सरकार से इससे संबंधित कोई मांग की है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस दस्तावेज को देशमुख 31 अक्तूबर से शुरू करके 8 नवंबर तक बांटते हैं। इस दौरान सिख अकेले छोड़ दिए जाते हैं। सचाई ये है कि 5 से लेकर 10 नवंबर के बीच सबसे ज्यादा सिखों की हत्याएं हुई थीं। लेकिन देशमुख पर इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ा।

नाना जी देशमुख मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे और संघ ने उन्हें अपने राजनीतिक संगठन के मोर्चे जनसंघ पर तैनात किया था। 1977 में वो सांसद भी बने थे। उन्होंने अपना चुनाव यूपी के बलरामपुर से जीता था। हालांकि बाद में उन्होंने राजनीति से सन्यास ले लिया और खुद चित्रकूट में आश्रम खोल लिए। फिर जीवन के आखिरी वक्त तक वो यहीं रहे। उनका एक आश्रम यूपी के गोंडा में भी स्थित था।